श्री मैरीम्बम पृथ्वीराज एलियास पृथ्वीराज सिंह

बनाम

श्री पुखरेम शरतचंद्र सिंह

(सिविल अपील संख्या2649/2016)

28 अक्टूबर, 2016

[अनिल आर. डेव और एल. नागेश्वर राव, न्यायाधिपति।]

चुनाव कानूनः

विधान सभा चुनाव-निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार- उम्मीदवार द्वारा चुनाव याचिका जो चुनाव हार गए, लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देते हुए उनकी शैक्षिक योग्यता और उनके नामांकन की अनुचित स्वीकृति के संबंध में झूठी घोषणा का आरोप लगाते हुए-चुनाव याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की कि उसे निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए -उच्च न्यायालय ने लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया- हालांकि, उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित करने से इनकार कर दिया-चुनाव याचिकाकर्ता और लौटे उम्मीदवार द्वारा क्रॉस-अपील- ठहराया गया*:* लौटाए गए व्यक्ति द्वारा फॉर्म *26* में दी गई शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत घोषित की गई मानी जाएगी -शैक्षणिक योग्यता की गलत घोषणा महत्त्वपूर्ण है- केवल यह निष्कर्ष निकालना कि नामांकन की अनुचित स्वीकृति हुई है, इस घोषणा के लिए पर्याप्त नहीं है कि चुनाव अन्तर्गत धारा *100 (1) (*डी*)* शून्य है -और सबूत होना चाहिए और यह दलील दी जानी चाहिए कि लौटे उम्मीदवार का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था-लेकिन अगर मैदान में केवल दो उम्मीदवार हैं तो इस तरह के सबूत की आवश्यकता नहीं है-वर्तमान मामले में, चुनाव याचिकाकर्ता के लिए यह साबित करने के लिए आवश्यक नहीं था कि चुनाव के परिणाम, जहां तक

इसका संबंध है, लौटने वाले उम्मीदवार को उनके नामांकन की अनुचित स्वीकृति से भौतिक रूप से प्रभावित किया गया है क्योंकि केवल दो उम्मीदवार थे चुनाव लड़ने में -उच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग में, चुनाव याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित करने से सही ढंग से इनकार कर दिया गया था क्योंकि वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था -चुनाव याचिकाकर्ता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था और चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इस तरह का अधिकार नहीं था- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1951*-एस. एस. *100(1)* (डी), ए *36(4), 53(2)* और *80*ए।

उच्च न्यायालय - अंतर्निहित शक्तियाँ - का प्रयोग - चुनाव याचिका पर सुनवाई करते समय- ठहराया: चुनाव याचिका पर सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय एक 'प्राधिकरण' नहीं है और चुनाव याचिका पर विचार करते समय यह उच्च न्यायालय ही रहता है- उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को दूर नहीं किया जाता है चुनावी विवादों का निपटारा करते समय- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, *1951*-एस.एस. *53(2)* और *80*ए.

न्यायालय ने अपील खारिज़ करते हुए ठहराया:

<u>सिविल अपील संख्या 2649/2016</u>

1.1 भारत के चुनाव आयोग ने **28.06.2002** को एक प्रेस नोट ज़ारी किया जिसमें भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ था, जिसमें यह माना गया था कि पांच पहलुओं पर मतदाता को जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। पाँच पहलुओं में से एक पहलू उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा **28.06.2002** को एक आदेश ज़ारी किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि फैसले में उल्लेखित पांच

पहलुओं से संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत की जानी है। पांच पहलुओं में से किसी पर अधूरी जानकारी प्रदान करना या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण चरित्र का दोष माना जाएगा। [अनुच्छेद 15][699-ई-एफ]

1.2 प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। अधिनियम, नियमों और फॉर्म 26 के प्रावधानों से यह भी स्पष्ट है कि उम्मीदवारों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में सही जानकारी देने का कर्तव्य है। [अनुच्छेद 17][700-बी-सी]

1.3 शपथ पत्र में अपीलकर्ता की शैक्षणिक योग्यता संबंधी घोषणा को लिपिकीय त्रुटि नहीं कहा जा सकता। यह एक बार की गई गलती नहीं है। 2008 से अपीलकर्ता यह बयान दे रहा था कि उसके पास एमबीए की डिग्री है। फॉर्म 26 में दाखिल हलफनामे में उनके द्वारा दी गई जानकारी झूठी घोषणा मानी जाएगी। उन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी घोषणा के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज़ पेश करने का अवसर दिया गया था। कम से कम उस समय तो उसे निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना ही चाहिए कि घोषणा में एक त्रुटि आ गई है। उन्होंने ऐसा नहीं किया । यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित झूठी घोषणा पर्याप्त प्रकृति की नहीं है। [अनुच्छेद 18][701-सी-ई]

किसन शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत 2014 (14) एससीसी 162; भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 (5) एससीसी 294: 2002 (3) एससीआर 696; रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य 2014 (14) एससीसी189: 2013 (9) एससीआर 360 - पर निर्भर किया गया।

2.1 किसी निर्वाचित उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति और किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति के बीच अंतर है। उन मामलों में

भी अंतर है जहां मैदान में केवल दो उम्मीदवार हैं और ऐसी स्थिति जहां दो से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यदि निर्वाचित उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया पाया जाता है, तो यह आवश्यक है कि चुनाव याचिकाकर्ता को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोट उसके पक्ष में पड़े होते। दूसरी ओर, यदि निर्वाचित उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति हुई है, तो इस बात के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है कि चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है क्योंकि यदि निर्वाचित उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार नहीं किया जाता तो वह चुनाव नहीं लड़ पाता। प्रतिवादी के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि चुनाव के परिणाम से जहां तक बात आती है कि लौटे उम्मीदवार पर उसके नामांकन की अनुचित स्वीकृति से भौतिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि चुनाव लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार थे और यदि अपीलकर्ता का नामांकन घोषित किया जाता है अनुचित तरीके से स्वीकार किए जाने पर, उसके चुनाव को बिना किसी और जांच के रद्द करना होगा और मैदान में बचा एकमात्र उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार होगा। [अनुच्छेद 22][706-ए-डी]

2.2 इस प्रकार, केवल यह पता लगाना कि नामांकन की अनुचित स्वीकृति हुई है, यह घोषणा करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि धारा 100(1)(डी) के तहत चुनाव शून्य है। आगे यह दलील और सबूत देना होगा कि लौटे उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। लेकिन एक निर्वाचित उम्मीदवार के नामांकन की स्थिति में किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी कि अनुचित तरीके से स्वीकार किए जाने के रूप में घोषित किया जा रहा है, खासकर ऐसे मामले में जहां मैदान में केवल दो उम्मीदवार हैं। यदि निर्वाचित उम्मीदवार का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया घोषित किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह चुनाव नहीं लड़ सकता था और निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था,

इसे आगे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। [अनुच्छेद 23][708-जी-एच; 709-ए-बी]

<u>सिविल अपील संख्या 2829/2016</u>

3. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को यह राहत देने से इनकार कर दिया कि उसे निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता, चुनाव परिणाम के बाद, भाजपा में शामिल होने के बाद घोषणा का हकदार नहीं था, क्योंकि उसने राकांपा की ओर से चुनाव लड़ा था। उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ संख्या 2 में व्यक्त कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा। अधिनियम के धारा 53(2) को देखते हुए ऐसा कहना सही नहीं है अधिनियम के धारा 53(2) के अनुसार, अपीलकर्ता को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए था क्योंकि प्रतिवादी/निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित किए जाने के बाद वह मैदान में एकमात्र व्यक्ति था। उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 80(ए) में चुनाव याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है। चुनाव याचिका पर सुनवाई करने वाला उच्च न्यायालय एक 'प्राधिकरण' नहीं है और चुनाव याचिका पर सुनवाई करते समय वह उच्च न्यायालय ही रहता है। जब चुनावी विवादों का फैसला सुनाया जाता है तो उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति छीन नहीं ली जाती है। उच्च न्यायालय की शक्ति पर 53(2) के होने से रोक नहीं है। उच्च न्यायालय ने उस विसंगतिपूर्ण स्थिति पर विचार किया है जो किसी एक पार्टी के उम्मीदवार द्वारा पक्ष परिवर्तन करने के बाद निर्वाचित घोषित किए जाने से उत्पन्न होगी। उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किये गये विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। [अनुच्छेद 27, 28, और 29][710-डी-एच; 711-ए, सी-डी]

दुरई मुथुस्वामी बनाम. एन. नचियप्पन और अन्य 1973 (2) एससीसी 45: 1974 (1) एससीआर 40; जगजीत सिंह बनाम धर्मपाल सिंह 1995 तितम्बा (1) एससीसी 422; वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चन्द्र 1955 (1) एससीआर 509; किसान शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत 2014 (14) एससीसी 162: 2014 (7) एससीआर 258 - पर निर्भर किया।

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2003 (4) एससीसी 399: 2003 (2) एससीआर 1136; सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा हरि कृष्ण लाल बनाम बाबू लाल मरांडी 2003 (8) एससीसी 613: 2003 (4) तितम्बा एससीआर 1170 ; मगनी लाल मंडल बनाम बिष्णु देव भंडारी 2012 (3) एससीसी 314: 2012 (1) एस. सी. आर. 527; शंभू प्रसाद शर्मा बनाम चरणदास महांत और अन्य 2012 (11) एससीसी 390:2012(6) एससीआर 356; टी.दीन.दयाल बनाम ए.पी.उच्च न्यायालय 1997 (7) एस. सी. सी. 535: 1997 (4) तितम्बा एस. सी. आर. 39, हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी 2001 (8) एससीसी 233: 2001 (3) तितम्बा एस. सी. आर. 38-संदर्भित।

<u>केस लॉज संदर्भ</u>

1974 (1) एससीआर 40	निर्भर	अनुच्छेद 6
1995 तितम्बा (1) एससीसी 422	निर्भर	अनुच्छेद 7,22
2002 (3) एससीआर 696	निर्भर	अनुच्छेद 7
2003 (2) एससीआर 1136	संदर्भित	अनुच्छेद 7
2014 (7) एससीआर 258	निर्भर	अनुच्छेद 7,16,22

2013 (9) एससीआर 360	निर्भर	अनुच्छेद 7
2001 (3) तितम्बा एससीआर 38	संदर्भित	अनुच्छेद 7,28
2012 (1) एससीआर 527	संदर्भित	अनुच्छेद 19
2012 (6) एससीआर 356	संदर्भित	अनुच्छेद 19
1955 (1) एससीआर 509	निर्भर	अनुच्छेद 22
1997 (4) तितम्बा एससीआर 39	संदर्भित	अनुच्छेद 29

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2649 /2016

चुनाव याचिका संख्या 1/2012 में इंफाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.02.2016 से

साथ में

सी. ए. नंबर 2829/2016

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, सपम विश्वजीत मैतेई, नरेश कुमार गौड़, मानव वोहरा, सुश्री पूनम कुमारी, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

श्रीमति मीनाक्षी अरोड़ा,वरिष्ठ अधिवक्ता, लेनिन हिजाम, वासव ए., राहुल जोशी, एडी तंबोली, एस. गौतमन, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए ।

न्यायालय का निर्णय एल नागेश्वर राव, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया

<u>सिविल अपील संख्या **2649/2016**</u>

1. अपीलकर्ता ने इम्फाल में मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर यह अपील दायर की है, जिसके द्वारा मोइरांग विधानसभा क्षेत्र से मणिपुर विधान सभा के लिए उसका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया था।

2. 04.01.2012 को 10वीं मणिपुर विधान सभा के चुनाव के लिए अधिसूचना ज़ारी की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) से संबंधित अपीलकर्ता और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) द्वारा प्रायोजित प्रतिवादी ने निर्धारित समय के भीतर अपना नामांकन दाखिल किया। कोई अन्य नामांकन दाखिल नहीं किया गया। प्रतिवादी ने जांच के समय अपीलकर्ता के नामांकन पर इस आधार पर आपत्ति जताई कि अपीलकर्ता द्वारा शैक्षिक योग्यता से संबंधित गलत घोषणा की गई थी। निर्वाचन अधिकारी ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह फॉर्म 26 के तहत दायर हलफनामे में घोषित अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण में दस्तावेज़ जमा करे। अपीलकर्ता अपनी शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज़ पेश करने में विफल रहा, जिसके बावजूद निर्वाचन अधिकारी ने अपीलकर्ता नामांकन स्वीकार कर लिया। मतदान 28.01.2012 को हुआ और वोटों की गिनती 06.03.2012 को हुई। परिणाम उसी दिन घोषित कर दिया गया। अपीलकर्ता को 14,521 वोट मिले और प्रतिवादी को 13,363 वोट मिले। अपीलकर्ता को मोइरांग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया।

3. प्रतिवादी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक चुनाव याचिका दायर करके अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती दी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि अपीलकर्ता का चुनाव अमान्य था, प्रतिवादी को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के खिलाफ़ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 125-ए और 127 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नामांकन की

अनुचित स्वीकृति के आधार के अलावा, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के खिलाफ़ भ्रष्ट आचरण का भी आरोप लगाया।

4. अपीलकर्ता ने झूठी घोषणा के आरोप से इनकार किया। अपीलकर्ता के अनुसार, उनके द्वारा की गई घोषणा कि उन्होंने 2004 में मैसूर विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) पास किया है, एक लिपिकीय त्रुटि थी। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनावी कदाचार के आरोप छोड़ दिये। उच्च न्यायालय ने छह मुद्दे तय किये जो इस प्रकार हैं:

i) "क्या *27*वें मोइरांग एसी के निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिवादी के नामांकन पत्र को अवैध रूप से स्वीकार कर लिया है या नहीं*?*

ii) क्या *27*वें मोइरांग ए/सी के आर.ओ. द्वारा प्रतिवादी के नामांकन पत्र को स्वीकार करने से प्रतिवादी का चुनाव वास्तव में प्रभावित हुआ था या नहीं*?*

iii) क्या प्रतिवादी ने फॉर्म में उच्चतम शिक्षा योग्यता के संबंध में गलत हलफनामा दायर किया था*,* जिसमें प्रतिवादी ने *"*एमबीए मैसूर विश्वविद्यालय*"* का उल्लेख किया था या क्या यह केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी*?*

iv) क्या याचिका में भौतिक तथ्यों का अभाव है या नहीं*?*

v) क्या याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के प्रत्येक पृष्ठ पर *"*याचिका की सत्य प्रति प्रमाणित*"* शब्द नहीं डालने पर चुनाव याचिका खारिज़ की जा सकती है या नहीं*;* या प्रतिवादी द्वारा अपने लिखित बयान में उठाए गए किसी दोष पर*?*

vi) क्या याचिकाकर्ता रिट याचिका में दावा की गई राहत का हकदार है*?"*

5. मुद्दा क्रमांक 5 याचिका का सत्यापन ठीक से नहीं किये जाने से संबंधित है। चुनाव याचिका की विचारणीयता पर अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति यह थी कि

चुनाव याचिका के केवल पहले पन्ने पर "सच्ची प्रतिलिपि होने के लिए सत्यापित" शब्द थे। अंक क्रमांक 5 का उत्तर प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में झूठा हलफनामा दायर करने से संबंधित मुख्य विवाद पर विस्तृत तरीके से विचार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता ने फॉर्म 26 दाखिल किया था जिसमें उसने 2004 में मैसूर विश्वविद्यालय से एमबीए के रूप में अपनी शैक्षिक योग्यता का उल्लेख किया था। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और पक्षों द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता द्वारा की गई घोषणा फॉर्म 26 में मैसूर विश्वविद्यालय से एमबीए के रूप में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया था जो गलत था। अपीलकर्ता की यह दलील कि फॉर्म 26 में त्रुटि लिपिकीय त्रुटि के कारण थी, खारिज़ कर दी गई। अपीलकर्ता की यह दलील कि शैक्षिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना कोई ठोस प्रकृति का दोष नहीं है, को भी खारिज़ कर दिया गया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी यह दलील देने और यह साबित करने में विफल रहा कि परिणाम 'भौतिक रूप से प्रभावित' था जैसा कि अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) के तहत आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने उक्त तर्क को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि मैदान में केवल दो उम्मीदवार थे, ऐसी स्थिति में यह साबित करना आवश्यक नहीं था कि लौटे उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यदि यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था, तो उसके चुनाव का परिणाम स्वतः ही भौतिक रूप से प्रभावित हो जाएगा। उपरोक्त कारणों के आधार पर उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। अपीलकर्ता ने उसी को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है।

6. हमने अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि और प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा को सुना है। श्री गिरि ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित घोषणा केवल एक लिपिकीय त्रुटि थी और इसे झूठी घोषणा नहीं कहा जा सकता। किसी भी स्थिति में, शैक्षिक योग्यता की घोषणा में कोई ठोस प्रकृति का दोष नहीं है जिसके कारण उसका नामांकन अस्वीकार किया जा सके। श्री गिरी ने यह भी कहा कि चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (i) और (iv) के तहत दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव याचिका में न तो कोई दलील है और न ही सबूत है कि अपीलकर्ता के नामांकन की अनुचित स्वीकृति ने परिणाम को प्रभावित किया है। श्री गिरि के अनुसार, अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना अपीलकर्ता के चुनाव को उसके नामांकन की अनुचित स्वीकृति के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। उन्होंने दुरई मुथुस्वामी बनाम एन. नचियप्पन और अन्य ***1973 (2)*** एससीसी ***45*** का हवाला दिया कि उक्त निर्णय को उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। उन्होंने उक्त निर्णय को इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होने के रूप में अलग करने का प्रयास करते हुए कहा कि यह अधिनियम की धारा 9-ए के तहत अयोग्यता का मामला था। उन्होंने आगे कहा कि उक्त मामला अधिनियम की धारा 100 (1) (ए) के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि चुनाव को धारा 100 (1) (ए) से (सी) के तहत चुनौती दी जाती है, तो यह दलील देने या साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था, जबकि धारा 100 (1) (डी) के तहत दायर याचिका में यह अनिवार्य है।

7. विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने चुनाव याचिका में दलील दी कि अपीलकर्ता के नामांकन की अनुचित स्वीकृति से चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। उसने हमें मौखिक और दस्तावेज़ी दोनों

दलीलों और सबूतों से अवगत कराया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि अपीलकर्ता द्वारा शैक्षिक योग्यता की घोषणा कोई गलती नहीं थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यही घोषणा अपीलकर्ता द्वारा तब भी की गई थी जब उसने 2008 में विधान सभा का पिछला चुनाव लड़ा था। उसने अपीलकर्ता द्वारा की गई घोषणा से संबंधित विरोधाभासी रुख पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह दिखाना जरूरी नहीं है कि जब एक सीट के लिए केवल दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे तो चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुरई मुथुस्वामी (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा किया, जो उनके अनुसार, जगजीत सिंह बनाम धरम पाल सिंह में अनुमोदित किया गया था, जिसकी रिर्पोट 1995 तितम्बा (1) एससीसी 422 में दी गई थी। उन्होंने आगे भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, रिपोर्ट किया गया 2002 (5) एससीसी 294 पर निर्भर किया, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रिर्पोट किया गया 2003 (4) एससीसी 399, किसान शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रय सावंत, रिपोर्ट किया गया 2014 (14) एससीसी 162 और रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य 2014 (14) एससीसी 189 में अपनी दलील के समर्थन में रिपोर्ट दी गई कि एक मतदाता को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का अधिकार है और किसी भी झूठी या गलत घोषणा के परिणामस्वरूप उम्मीदवार का नामांकन खारिज़ कर दिया जाएगा। सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने यह तर्क देने के लिए 2003 में रिर्पोट किया गया हरि कृष्ण लाल बनाम बाबू लाल मरांडी2003 (8) एससीसी 613 का भी हवाला दिया कि उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित झूठी घोषणा पर्याप्त प्रकृति का दोष है।

8. इस अपील में हमारे विचार के लिए दो मुद्दे हैं जो हैं:

(ए) क्या शैक्षिक योग्यता से संबंधित झूठी घोषणा नामांकन की अस्वीकृति का कारण बनने वाली पर्याप्त प्रकृति दोष है?

(बी) क्या यह दलील देना और साबित करना आवश्यक है कि जब निर्वाचित उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया पाया गया तो परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ, इसके अलावा, जब चुनाव लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार हों?

9. अधिनियम के भाग V का अध्याय I उम्मीदवारों के नामांकन से संबंधित है। अधिनियम की धारा 33 नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन की आवश्यकताओं का प्रावधान करती है। निर्धारित प्रपत्र में पूरा नामांकन पत्र, जिस पर उम्मीदवार और निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किया गया हो, रिटर्निंग आधिकारी को सौंपा जाना चाहिए एक निर्धारित अवधि के भीतर। धारा 33-ए जो 2002 के अधिनियम 72 द्वारा 24.08.2002 से जोड़ी गई थी, यह मानती है कि एक उम्मीदवार को धारा 33 (1) के तहत उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अलावा अतिरिक्त जानकारी प्रदान करनी होगी। धारा 33-ए में उल्लेखित जानकारी उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास से संबंधित है। धारा 36 नामांकन की जांच से संबंधित है। धारा 36(4) जो इस मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"36. नामांकन की जांच *- (4)* रिटर्निंग अधिकारी किसी भी दोष के आधार पर किसी भी नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त प्रकृति का नहीं है।"

10. चुनाव आचरण नियम, 1961 का नियम 4 (ए) जो 03.09.2002 से डाला गया था, इस प्रकार है:

> "[*4*ए*.* नामांकन पत्र वितरित करते समय दाख़िल किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रपत्र*. -* उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक*,* जैसा भी मामला हो*,* रिटर्निंग अधिकारी को अधिनियम की धारा *33* उपधारा *(1)* के तहत नामांकन पत्र सौंपते समय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या

नोटरी फॉर्म *26* में, के समक्ष उम्मीदवार द्वारा शपथ लिया गया एक शपथ पत्र दाख़िल करेगा।]"

11. उम्मीदवार को अपने नामांकन पत्र के साथ फॉर्म 26 में निर्धारित एक हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें एक कॉलम शैक्षिक योग्यता से संबंधित है। चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार अधिनियम की धारा 100 में प्रदान किया गया है जो इस प्रकार है:

"***100.*** चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए आधार*.-*

[(1) उपधारा *(2)* के प्रावधानों के अधीन यदि *3 [*उच्च न्यायालय*]* की राय है-

*(*ए*)* कि अपने चुनाव की तारीख पर एक निर्वाचित संविधान या इस अधिनियम *9 [*या केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, *1963 (1963* का *20)* के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं था, या अयोग्य घोषित किया गया था। *];* या

*(*बी*)* किसी निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी निर्वाचित उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है*;* या

*(*सी*)* कि किसी भी नामांकन को अनुचित तरीके से खारिज़ कर दिया गया है*;* या

*(*डी*)* जहां तक चुनाव के नतीजे का सवाल है लौटाया गया उम्मीदवार, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

*(i)*अनुचित स्वीकृति या किसी नामांकन द्वारा, या

(ii) निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा *1 [*उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा*],* या

(iii) किसी वोट को अनुचित तरीके से स्वागत करने, इनकार करने या अस्वीकार करने या किसी ऐसे वोट को स्वीकार करने से जो शून्य हो, या

(iv) संविधान या इस अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का अनुपालन न करने से,

*[*उच्च न्यायालय*]* लौटे उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करेगा।*]*

[(2)] यदि *2 [*उच्च न्यायालय*]* की राय में, एक निर्वाचित उम्मीदवार को उसके चुनाव एजेंट के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया है *4 **** लेकिन *2 [*उच्च न्यायालय*]* संतुष्ट है -

*(*ए*)* कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया था, और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट के आदेशों और *5 [*सहमति के बिना*)* के विपरीत किया गया था*;*

*6 ******

*(*सी*)* कि उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए सभी उचित उपाय किए*;* और

(डी) अन्य सभी मामलों में चुनाव उम्मीदवार या उसके किसी भी एजेंट की ओर से किसी भी भ्रष्ट *7**** आचरण से मुक्त था,

तब *2 [*उच्च न्यायालय*]* निर्णय ले सकता है कि लौटे उम्मीदवार का चुनाव शून्य नहीं है।"

12. धारा 125-ए झूठा हलफनामा दाख़िल करने के लिए दंड का प्रावधान करती है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

***"[125*ए. झूठा हलफनामा दाख़िल करने के लिए जुर्माना, आदि–**

एक उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से चुनाव में निर्वाचित होने का इरादा रखता है।---

(1) धारा *33*ए की उपधारा *(1)* से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है*;* या

(ii) गलत जानकारी देगा जिसके बारे में वह जानता है या जिसके गलत होने पर विश्वास करने का उसके पास कारण है*;* या

(iii) धारा *33* की उप-धारा *(1)* के तहत दिए गए अपने नामांकन पत्र में या अपने हलफनामे में, जो कि धारा *33* ए की उप-धारा *(2)* के तहत दिया जाना आवश्यक है, कोई भी जानकारी छिपाता है, जैसा भी मामला हो, , तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, छह महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।*]*"

13. सर विंस्टन चर्चिल ने सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप में मतदाता के महत्व को रेखांकित करते हुए इस प्रकार कहा:

"लोकतंत्र को दी जाने वाली सभी श्रद्धांजलियों में सबसे नीचे वह छोटा आदमी है, जो एक छोटे से बूथ में जाता है, एक छोटी सी पेंसिल के साथ, थोड़े से कागज पर एक छोटा सा क्रॉस बनाता है - कोई भी बयानबाजी या बड़ी चर्चा संभवतः मुद्दे की बात के अत्याधिक महत्व को कम नहीं कर सकती है।"

14. भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा) में इस न्यायालय ने माना कि मतदाता को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। मतदाता के पास यह निर्णय लेने का विकल्प होता है कि उसे आपराधिक मामले में शामिल व्यक्ति के पक्ष में वोट देना चाहिए या नहीं। उसे यह निर्णय लेने का भी अधिकार है कि किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए शैक्षणिक योग्यता रखना या संपत्ति रखना प्रासंगिक है या नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (सुप्रा) के फैसले के अनुसार, एक अध्यादेश द्वारा अतिरिक्त जानकारी का अधिकार प्रदान करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में धारा 33-ए शामिल की गई थी। उक्त अध्यादेश की चुनौती को इस न्यायालय द्वारा पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (सुप्रा) में निपटाया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया था:

"*78.* उपरोक्त चर्चा से जो उभरकर सामने आता है उसे इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है*:*

*(*डी*)* यह तर्क कि चूंकि किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा किसी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त को जानने का कोई विशिष्ट मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है*,* इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हैं*,* प्रथम दृष्टया*,* बिना किसी तत्त्व के।

किसी विशेष उम्मीदवार के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में, वैधानिक प्रावधान दलों के संबंधित अधिकारों को नियंत्रित करेंगे। हालाँकि, किसी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त को जानने का मतदाताओं का मौलिक अधिकार चुनाव कानून के तहत वैधानिक अधिकारों से स्वतंत्र है। मतदाता इस देश का प्रथम नागरिक है और उसे वैधानिक अधिकारों के अलावा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं। एक लोकतांत्रिक समाज के सदस्यों को पर्याप्त रूप से सूचित किया जाना चाहिए ताकि वे उन लोगों के पक्ष में समझदारी से अपना वोट दे सकें जो उन पर शासन करना चाहते हैं। वोट देने का अधिकार तब तक अर्थहीन होगा जब तक कि नागरिकों को किसी उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के बारे में अच्छी तरह से जानकारी नहीं दी जाती। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जनता की नज़र और जांच के संपर्क में आना हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शुद्ध करने और सक्षम विधायिका बनाने के सबसे अचूक साधनों में से एक है।

15. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि भारत के चुनाव आयोग ने 28.06.2002 को एक प्रेस नोट ज़ारी किया था जिसमें भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ था जिसमें यह कहा गया था कि जानकारी मतदाता को पांच पहलुओं पर जानकारी देनी होगी। पांच पहलुओं में से एक पहलू उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा 28.06.2002 को एक आदेश ज़ारी किया गया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि फैसले में उल्लेखित पांच पहलुओं से संबंधित पूरी जानकारी प्रस्तुत की जानी है। पांच

पहलुओं में से किसी पर अधूरी जानकारी प्रदान करना या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण प्रकृति का दोष माना जाएगा।

16. रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य में (सुप्रा) इस न्यायालय ने माना कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने आपराधिक इतिहास, संपत्ति और देनदारियों और शैक्षिक योग्यता के संबंध में प्रासंगिक जानकारी के साथ एक हलफनामा दायर करने के लिए बाध्य है। उक्त निर्णय में मतदाता के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार को दोहराया गया था और यह माना गया कि खाली विवरण के साथ हलफनामा दाखिल करने से हलफनामा निरर्थक हो जाएगा। 2014 में रिपोर्ट किया गया <u>किसान शंकर कथोर बनाम अरुण दत्तात्रय सावंत **2014 (14)** एससीसी पेज **162**</u> में इस न्यायालय ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या अपीलकर्ता के लिए नामांकन फॉर्म में मांगी गई जानकारी का खुलासा करना अनिवार्य था और क्या उसका गैर-प्रकटीकरण नामांकन को अवैध और शून्य कर देगा। यह माना गया कि आवश्यक जानकारी न देना छिपाना/प्रकटीकरण न करने के समान होगा।

17. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। अधिनियम, नियम और फॉर्म 26 के प्रावधानों से यह भी स्पष्ट है कि उम्मीदवारों पर उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में सही जानकारी देने का कर्तव्य है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता ने मैसूर विश्वविद्यालय में एमबीए की पढ़ाई नहीं की। अपीलकर्ता का मामला यह है कि मैसूर विश्वविद्यालय से एमबीए का संदर्भ एक लिपिकीय त्रुटि थी। अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उसने हमेशा मैसूर विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा एमबीए करने के बारे में सोचा था। लेकिन, असल में उन्होंने कोर्स नहीं किया। जिस प्रश्न का निर्णय किया जाना है वह यह है कि क्या फॉर्म 26 में उनके द्वारा दी गई घोषणा उनके नामांकन को अस्वीकार करने वाली

पर्याप्त प्रकृति की त्रुटि होगी। अधिनियम की धारा 36 (4) में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारी किसी ऐसे दोष के आधार पर नामांकन पत्र को अस्वीकार नहीं करेगा जो पर्याप्त प्रकृति का नहीं है। अपीलकर्ता द्वारा 2012 में दायर फॉर्म 26 में की गई घोषणा कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है जैसा कि उसने तर्क दिया है। अपीलकर्ता ने 2008 में उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उसके द्वारा फॉर्म 26 में दायर हलफनामे में यह बताया गया है उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने 2004 में मैसूर विश्वविद्यालय से एमबीए पास किया है। इस चुनाव याचिका में मुख्य परीक्षा के माध्यम से उनके द्वारा दायर हलफनामे में, अपीलकर्ता ने कहा कि उनका नामांकन पत्र और संलग्न हलफनामा उनके एजेंट पीएच. शामू सिंह के निर्देश पर वकील चकपम बिमोलचंद्र सिंह द्वारा तैयार और दायर किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके वकील ने निर्धारित शपथ पत्र अपनी हस्तलिखित में भरा। अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि उसने हलफनामे की सामग्री को पढ़े बिना उस पर हस्ताक्षर किए और उसे त्रुटि के बारे में तभी पता चला जब प्रतिवादी ने नामांकन पर आपत्ति जताई। अपीलकर्ता ने आगे कहा कि वह 2007 तक प्रोजॉन, इंफोसिस कंपनी और आईबीएम में काम कर रहा था और उसकी नौकरी के कारण कई स्थानीय दोस्तों और बुजुर्गों को लगता था कि वह एमबीए डिग्री धारक है। उनके चुनाव एजेंट को भी लगा कि उन्होंने एमबीए की डिग्री धारण कर रखी है जिसके कारण उन्होंने अधिवक्ता चकपम बिमोलचंद्र सिंह को निर्देश दिया कि वे शपथ पत्र के कॉलम 9 को यह कहते हुए भरें कि अपीलकर्ता एमबीए डिग्री धारक है। अपनी जिरह में, अपीलकर्ता ने अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित सवालों के गोल-मोल जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से एमबीए किया है या नहीं और उन्हें यह भी याद नहीं है कि उनके पास एमबीए की डिग्री है या नहीं । चकपम बिमोलचंद्र सिंह, जिनकी जिरह में डीडब्ल्यू-3 के रूप में जांच की गई थी, ने फॉर्म 26 में प्रविष्टियां भरने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव एजेंट

शामू सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर अपीलकर्ता की शैक्षणिक योग्यताएं दर्ज कीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब अपीलकर्ता ने हलफनामे पर हस्ताक्षर किए तो वह शपथ आयुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं थे।

18. अपीलकर्ता का यह तर्क कि शपथ पत्र में उसकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित घोषणा एक लिपिकीय त्रुटि है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह एक बार की गई गलती नहीं है। 2008 से अपीलकर्ता यह बयान दे रहा था कि उसके पास एमबीए की डिग्री है। फॉर्म 26 में ददाख़िल हलफनामे में उनके द्वारा दी गई जानकारी झूठी घोषणा मानी जाएगी। उक्त झूठी घोषणा को ऐसा दोष नहीं कहा जा सकता जो तत्वहीन है। उन्हें निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी घोषणा के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज़ पेश करने का अवसर दिया गया था। कम से कम उस समय उन्हें निर्वाचन अधिकारी को सूचित करना चाहिए था कि घोषणा में एक त्रुटि आ गई है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित झूठी घोषणा पर्याप्त प्रकृति की नहीं है। यह अब कोई शर्त नहीं रह गई है कि प्रत्येक उम्मीदवार को मतदाता के सूचना के अधिकार का लाभ उठाने के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता का खुलासा करना होगा। अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में झूठी घोषणा करने के बाद, अपीलकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि घोषणा पर्याप्त प्रकृति की नहीं है। ऊपर बताए गए कारणों के लिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को बरकरार रखते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा की गई शैक्षणिक योग्यता से संबंधित झूठी घोषणा पर्याप्त प्रकृति की है।

19. अपीलकर्ता के विरुद्ध पहले प्रश्न का उत्तर देने के बाद, अब हम अगले बिंदु पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। धारा 100 (1) (ए) से (सी) क्रमशः अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण और नामांकन की अनुचित अस्वीकृति से संबंधित है जो चुनाव को रद्द करने का आधार है। धारा 100 (1) (डी) के तहत किसी चुनाव को रद्द करने के लिए

अनिवार्य शर्त यह है कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह निर्वाचित उम्मीदवार की बात है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। श्री गिरि का तर्क, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि भले ही यह माना जाता है कि अपीलकर्ता का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था, उसके चुनाव को किसी भी दलील या सबूत के अभाव में रद्द नहीं किया जा सकता है कि परिणाम नामांकन की अनुचित स्वीकृति से प्रभावित हुआ था। उन्होंने 2012 में रिर्पोट हुआ मगनी लाल मंडल बनाम बिष्णु देव भंडारी **2012 (3)** एससीसी पेज **314** पर निर्भर करते हुए कहा कि प्रत्येक दोष धारा 100 (1) (डी) के तहत चुनाव को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, बिना किसी सबूत के। लौटे उम्मीदवार के परिणाम पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ा। उन्होंने 2012 में रिर्पोट हुआ शंभू प्रसाद शर्मा बनाम चरणदास महंत और अन्य **2012 (11)** एससीसी पृष्ठ **390** का भी जिक्र किया जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया था:

> "*20.* इस आरोप पर आते हुए कि अन्य उम्मीदवारों ने भी उचित प्रारूप में हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे उनके नामांकन पत्रों की स्वीकृति अनुचित हो गई, हमें यह इंगित करने की आवश्यकता है कि अपीलकर्ता को न केवल ऐसी अनुचित स्वीकृति के लिए प्रासंगिक भौतिक तथ्यों का आरोप लगाना आवश्यक था , लेकिन आगे दावा किया गया है कि इस तरह की स्वीकृति से निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। चुनाव याचिका में ऐसा कोई दावा नहीं है। केवल अनुचित स्वीकृति यह मानते हुए कि ऐसी कोई भी अनुचित स्वीकृति अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा भौतिक तथ्यों के दावे द्वारा समर्थित थी, चुनाव याचिका की सुनवाई के लिए कार्रवाही के कारण का खुलासा नहीं करेगा गुण -दोष के आधार पर याचिका दायर करें, जब तक कि यह आरोप न लगाया

जाए कि इससे लौटे उम्मीदवार के परिणाम पर भौतिक प्रभाव पड़ा है।"

20. इसमें कोई विवाद नहीं है कि किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति के आधार पर बिना किसी दलील और सबूत के कि निर्वाचित उम्मीदवार का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था चुनाव को रद्द नहीं किया जा सकता है। विचार करने की बात यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के परिणाम के भौतिक रूप से प्रभावित होने के तथ्य की दलील और सबूत से संबंधित कानून उस मामले पर लागू होता है जहां नामांकन निर्वाचित उम्मीदवार को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया घोषित किया गया है। इस मामले के तथ्यों के समान स्थिति दुरई मुथुस्वामी के मामले में इस न्यायालय के विचार के लिए उत्पन्न हुई। इस मामले से विस्तार से निपटना आवश्यक है क्योंकि अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है और उक्त मामले में निष्कर्ष को ओबिटर के रूप में माना जाना चाहिए।

21. दुरई मुथुस्वामी के मामले के तथ्य, संक्षेप में, ये हैं कि चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता ने शंकरपुरम निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधान सभा का चुनाव लड़ा। उन्होंने प्रथम प्रतिवादी के चुनाव को लौटे उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति, 101 डाक मतपत्रों की अस्वीकृति, अयोग्य व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति, मृत व्यक्तियों के नाम पर मतदान और दोहरे मतदान के आधार पर चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को यह कहते हुए खारिज़ कर दिया कि याचिकाकर्ता यह आरोप लगाने और साबित करने में विफल रहा कि चुनाव के परिणाम धारा 100 (1) (डी) के अनुसार प्रथम प्रतिवादी के नामांकन की अनुचित स्वीकृति से प्रभावित हुए थे। याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई सिविल अपील को दुरई मुथुस्वामी (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया था:

"3. इस प्रश्न पर विचार करने से पहले कि क्या विद्वान न्यायाधीश का मानना सही था कि वह इस प्रश्न पर नहीं जा सकते कि क्या प्रथम प्रतिवादी का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है क्योंकि चुनाव याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं था कि चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ हो ऐसी अनुचित स्वीकृति के परिणामस्वरूप, हम कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर कर सकते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत, किसी भी चुनाव पर सवाल उठाने वाली एक चुनाव याचिका धारा 100 की उप धारा (1) और धारा 101 में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है। शेष धारा का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। धारा 83(1)(ए) के तहत, जहां तक इस मामले के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है, एक चुनाव याचिका इसमें उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है। धारा 100(1) के तहत यदि उच्च न्यायालय की राय है-

(ए) कि अपने चुनाव की तारीख पर एक निर्वाचित संविधान या इस अधिनियम के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं था, या अयोग्य घोषित किया गया था...

(बी)-(सी)***

(डी) कि चुनाव का नतीजा, जहां तक यह एक निर्वाचित उम्मीदवार से संबंधित है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है-

(i) किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति से, या

(ii)-(iii)***

उच्च न्यायालय निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित कर देगा। इसलिए, धारा *100* की आवश्यकता यह है कि उच्च न्यायालय को एक निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने से पहले यह राय रखनी चाहिए कि चुनाव का परिणाम, जहां तक यह एक निर्वाचित उम्मीदवार की बात है, किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। धारा *83* के तहत केवल उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण आवश्यक था जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है। इस मामले में अपीलकर्ता ने ऐसा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रथम प्रतिवादी के नामांकन की अनुचित स्वीकृति के कारण चुनाव शून्य है और दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि प्रथम प्रतिवादी अयोग्यता से पीड़ित था जो धारा *9*-ए के तहत आएगा। इसीलिए इसे अनुचित स्वीकृति कहा गया। हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि इस मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के लिए यह भी आरोप लगाना आवश्यक था कि चुनाव का परिणाम, जहां तक इसका सवाल है, पहले प्रतिवादी के नामांकन की अनुचित स्वीकृति से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। इस मामले की परिस्थितियों से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है। केवल एक सीट भरी जानी थी और केवल दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। यदि यह आरोप स्वीकार कर लिया जाता है कि पहले प्रतिवादी का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार कर लिया गया है, तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि अपीलकर्ता को वैसे ही चुना गया होगा जैसे वह वैध रूप से नामांकित एकमात्र उम्मीदवार था। इसलिए, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है कि जहां तक बात निर्वाचित उम्मीदवार की है, तो

उसके नामांकन की अनुचित स्वीकृति के कारण चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है, क्योंकि ऐसी अनुचित स्वीकृति के बिना वह चुनाव में खड़ा नहीं हो पाता या निर्वाचित घोषित किया जाए. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि प्रथम प्रतिवादी के नामांकन की अनुचित स्वीकृति के कारण चुनाव शून्य हो गया था। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मामले में यदि दो से अधिक उम्मीदवार हैं और पराजित उम्मीदवारों में से एक का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार कर लिया गया है, तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसे अनुचित स्वागत से लौटे उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव पड़ा है। ऐसे में यह सवाल उठेगा कि जिस हारे हुए उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया था, अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया होता तो उसके पक्ष में डाले गए वोटों का क्या होता। उस स्थिति में चुनाव को चुनौती देने वाले व्यक्ति के लिए न केवल आरोप लगाना आवश्यक होगा बल्कि यह साबित करना भी आवश्यक होगा कि चुनाव के परिणाम अन्य पराजित उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति से भौतिक रूप से प्रभावित हुए थे। जब तक वह यह साबित करने में सफल नहीं हो जाता कि जिस उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था, उसके पक्ष में डाले गए वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में जाते और उसे बहुमत मिलता, तो वह अपनी चुनाव याचिका में सफल नहीं हो सकता। धारा *100(1)(डी)(i)* ऐसी आकस्मिकता से संबंधित है। इसका उद्देश्य कोई सुविधाजनक सुविधा प्रदान करना नहीं है। इस तरह के मामले में तकनीकी दलील जहां

अनुचित नामांकन की स्वीकृति से चुनाव के भौतिक रूप से प्रभावित होने पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। "भौतिक रूप से प्रभावित" कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे निर्दिष्ट किया जाना है, बल्कि यह एक अनिवार्य आवश्यकता है जिस पर इस खंड में विचार किया गया है। कानून किसी सूत्र की मात्र पुनरावृत्ति पर विचार नहीं करता है। विद्वान न्यायाधीश उस आधार के बीच अंतर को नोटिस करने में विफल रहे हैं जिस पर चुनाव को शून्य घोषित किया जा सकता है और उन आरोपों के बीच जो ऐसे आधार के संबंध में चुनाव याचिका में आवश्यक हैं। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जिस आधार पर प्रथम प्रतिवादी का चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने धारा *83(1)(ए)* के तहत आवश्यक भौतिक तथ्य भी दिए थे। इसलिए, हमारी राय है कि विद्वान न्यायाधीश ने यह मानने में गलती की कि उनके लिए इस प्रश्न पर विचार करना सक्षम नहीं था कि क्या पहले प्रतिवादी का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था।" *(हमारे रेखांकित करते हुए)*

22. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि किसी निर्वाचित उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति और किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन की अनुचित स्वीकृति के बीच अंतर है। उन मामलों में भी अंतर है जहां मैदान में केवल दो उम्मीदवार हैं और ऐसी स्थिति जहां दो से अधिक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यदि निर्वाचित उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया पाया जाता है, तो यह आवश्यक है कि चुनाव याचिकाकर्ता को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोट उसके पक्ष में पड़े होंगे। दूसरी ओर, यदि नामांकन की अनुचित स्वीकृति निर्वाचित उम्मीदवार की है, तो

सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है कि चुनाव भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है क्योंकि निर्वाचित उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यदि उनका नामांकन स्वीकार नहीं किया गया था । प्रतिवादी के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि चुनाव के परिणाम से जहां तक बात आती है कि लौटे उम्मीदवार पर उसके नामांकन की अनुचित स्वीकृति से भौतिक प्रभाव पड़ा है क्योंकि चुनाव लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार थे और यदि अपीलकर्ता का नामांकन घोषित किया जाता है अनुचित तरीके से स्वीकार किए जाने पर, उसके चुनाव को बिना किसी और जांच के रद्द करना होगा और मैदान में बचा एकमात्र उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होने का हकदार होगा। दुरई मुथुस्वामी (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले को जगजीत सिंह बनाम धरम पाल सिंह, ***1995*** तितम्बा ***(1)*** एससीसी ***422*** पृष्ठ ***429*** में संदर्भित किया गया था जिसमें इसे निम्न रूप में रखा गया था:

> "*21.* विचारण न्यायाधीश ने माना है कि चूंकि याचिका में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि चुनाव का परिणाम अनुचित अस्वीकृति या वोटों की स्वीकृति से प्रभावित हुआ था, यह कार्रवाही के कारण से रहित है। हम इस बात से सहमत होने में असमर्थ हैं कि इस मामले के तथ्यों में ऐसे प्रकथन की अनुपस्थिति घातक है। जैसा कि इस न्यायालय ने बताया है, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां परिस्थितियों से स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है और अधिनियम की धारा *100 (1)(*डी*)* का उद्देश्य ऐसे मामले में एक सुविधाजनक तकनीकी दलील प्रदान करना नहीं है जहां चुनाव के परिणाम के कथित दुर्बलता से भौतिक रूप से प्रभावित होने के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है। *(*देखें*:* दुरई मुथुस्वामी बनाम एन नचियप्पन *[(1973) 2* एससीसी *45: (1974)*

1 एससीआर *40].)* वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका में कहा गया है कि वह केवल *80* वोटों के अंतर से हारे हैं। चुनाव याचिका में विभिन्न कथनों से यह स्पष्ट था कि अपीलकर्ता के वैध वोटों की संख्या, जिन्हें अनुचित तरीके से खारिज़ कर दिया गया था, *80* से कहीं अधिक है। चुनाव याचिका में निहित कथनों से यह स्पष्ट है कि यदि अपीलकर्ता सफल होता है अपना मामला स्थापित करने में, जैसा कि चुनाव याचिका में बताया गया है, इस चुनाव का नतीजा, जहां तक यह निर्वाचित उम्मीदवार से संबंधित है, भौतिक रूप से प्रभावित होगा।"

इस न्यायालय द्वारा वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चंद्रा **1955 (1)** एससीआर **509** मामले में यह व्यवस्था दी गई थी जो इस प्रकार है:

"9. प्रतिवादियों के विद्वान वकील मानते हैं कि यह साबित करने का भार कि नामांकन की अनुचित स्वीकृति ने चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया है, याचिकाकर्ता पर है, लेकिन उनका तर्क है कि प्रश्न तीन तरीकों में से एक में उठ सकता है*:*

(1) जहां जिस उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था, उसे लौटे उम्मीदवार और अगले सबसे अधिक वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के बीच के अंतर से कम वोट मिले थे,

(2) जहां ऊपर बताए गए व्यक्ति को अधिक वोट मिले, और

(3) जहां जिस व्यक्ति का नामांकन अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है वह स्वयं निर्वाचित उम्मीदवार है।

इस बात पर सहमति है कि पहले मामले में चुनाव के नतीजे पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर बर्बाद हुए सभी वोटों को सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार के वोटों में जोड़ दिया जाए तो इससे नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और निर्वाचित उम्मीदवार ही सीट पर बना रहेगा । अन्य दो मामलों में यह तर्क दिया गया है कि परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित होता है। जहां तक तीसरे मामले का संबंध है, यह आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि निष्कर्ष यही होगा। लेकिन हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि केवल यह तथ्य कि बर्बाद हुए वोट निर्वाचित उम्मीदवार और अगली सबसे अधिक संख्या में वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार के बीच वोटों के अंतर से अधिक हैं, यह आवश्यक निष्कर्ष निकालना होगा कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। यह एक ऐसा मामला है जिसे साबित करना होगा और इसे साबित करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर है। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि बर्बाद हुए सभी या अधिकांश वोट अगले सर्वोच्च उम्मीदवार को चले गए होंगे। किसी चुनाव में वोट डालना कई कारकों पर निर्भर करता है और किसी के लिए भी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किसी एक या दूसरे उम्मीदवार को कितने या किस अनुपात में वोट मिलेंगे। हालांकि यह माना जाना चाहिए कि ऐसे मामले में याचिकाकर्ता को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, धारा *100 (1) (सी)* द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्य से उसे मुक्त करना और सबूत के बिना यह मानना संभव नहीं है कि कर्तव्य पूरा हो गया है। यदि याचिकाकर्ता इस बिंदु पर अदालत को अपने पक्ष में निष्कर्ष निकालने

में सक्षम करने के लिए संतोषजनक सबूत पेश करने में विफल रहता है, तो अपरिहार्य परिणाम यह होगा कि न्यायाधिकरण उसके पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा और चुनाव को अनुमति देगा।" (हमारे रेखांकित करते हुए)।

इस न्यायालय ने किसान शंकर कथोरे बनाम अरुण दत्तात्रेय सावंत (सुप्रा) में इस मामले के समान स्थिति से निपटा। उस मामले में, महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा न करने के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी। निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा दायर अपील को इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार खारिज़ कर दिया गया:

"एक बार जब यह पाया जाता है कि यह अनुचित स्वीकृति का मामला था, क्योंकि इसमें गलत सूचना थी या भौतिक जानकारी को छिपाया गया था, तो कोई यह कह सकता है कि ऐसे मामले में अस्वीकृति का प्रश्न केवल बाद की तारीख़ के लिए टाल दिया गया था। जब न्यायालय ऐसा निष्कर्ष देता है , जिसके परिणामस्वरूप अस्वीकृति होती, प्रभाव वही होगा, अर्थात्, ऐसा उम्मीदवार चुनाव लड़ने का हकदार नहीं था और चुनाव शून्य है।"

23. केवल यह पता लगाना कि नामांकन की अनुचित स्वीकृति हुई है, यह घोषणा करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि चुनाव धारा 100 (1) (डी) के तहत वैध है। अभी और विनती और सबूत होना चाहिए कि निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रुप से प्रभावित था। लेकिन, निर्वाचित उम्मीदवार के नामांकन को अनुचित तरीके से स्वीकार किए जाने की स्थिति में किसी भी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी, खासकर ऐसे मामले में जहां मैदान में केवल दो उम्मीदवार हों। यदि

निर्वाचित उम्मीदवार का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया घोषित किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि वह चुनाव नहीं लड़ सकता था और निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था, इसे आगे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हमें श्री गिरि की इस दलील में दम नहीं मिला कि दुरई मुथुस्वामी (सुप्रा) का फैसला इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है। यह दलील भी सही नहीं है कि दुरई मुथुस्वामी अधिनियम की धारा 9-ए के तहत अयोग्यता का मामला है और इसलिए, यह इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, उस मामले में चुनाव याचिका धारा 100 (1) (डी) का अनुपालन न करने के आधार पर खारिज़ कर दी गई थी। उक्त निर्णय इस मामले पर पूरी तरह से सभी चारों तरफ लागू होता है। हम इस दलील में भी बल नहीं पाते हैं कि अधिनियम को सख्ती से समझा जाना चाहिए और धारा 100 (1) (डी) के तहत चुनाव को बिना दलील और सबूत के शून्य घोषित नहीं किया जा सकता है कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक बार जब यह घोषित कर दिया जाता है कि नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार कर लिया गया है, तो निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित होता है।

24. उपरोक्त कारणों से, सिविल अपील खारिज़ की जाती है। कोई लागत नहीं ।

<u>सिविल अपील संख्या **2829/2016**</u>

25. यह अपील याचिकाकर्ता द्वारा इंफाल में उच्च न्यायालय मणिपुर के दिनांक 29.02.2016 के फैसले के उस हिस्से को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में दायर की गई है, जिसके द्वारा यह राहत कि उसे निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए, खारिज़ कर दी गई थी। अपीलकर्ता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। प्रतिवादी संख्या 1 को 28.01.2012 को निर्वाचित घोषित किया गया था।

अपीलकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका में प्रथम प्रतिवादी के चुनाव को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने यह राहत भी मांगी कि उसे निर्वाचित घोषित किया जाए। ऐसी राहत को उच्च न्यायालय ने खारिज़ कर दिया था। इसलिए, यह अपील हुई।

26. चुनाव परिणाम दिनांक 28.01.2012 को घोषित होने के बाद, अपीलकर्ता ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। अपने साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के दौरान न्यायालय द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में, अपीलकर्ता ने कहा कि उसने 2013 के बाद के हिस्से में एनसीपी से इस्तीफा दे दिया था, वह भाजपा में शामिल हो गए और वह भाजपा के सदस्य बने रहे। जनवरी, 2016 में अपीलकर्ता ने चुनाव याचिका में संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया। उनका इरादा 23.12.2013 को एनसीपी से उनके निष्कासन से संबंधित अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ और निष्कासन आदेश को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति एनसीपी मणिपुर को दिए गए अभ्यावेदन को शामिल करने का था। वह इस तथ्य को भी रिकॉर्ड पर लाना चाहते थे कि भाजपा की सदस्यता के लिए उनका नामांकन 18.01.2016 को खारिज़ कर दिया गया था। उन्होंने आवेदन में आगे कहा कि एनसीपी द्वारा निष्कासन के आदेश को 21.01.2016 के एक आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

27. अपीलकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका में बहस 25.02.2016 को समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में एक निष्कर्ष दर्ज किया कि सभी लंबित विविध आवेदनों का निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से किया गया था और चुनाव याचिका का फैसला रिकॉर्ड पर मौजूदा सामग्री के आधार पर किया जाना था। चूंकि अपीलकर्ता द्वारा दायर विविध आवेदन पर विचार नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर मामले का फैसला किया, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि अपीलकर्ता ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में

शामिल हो गया। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई घोषणा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने माना कि भाजपा में शामिल होने के बाद अपीलकर्ता घोषणा का हकदार नहीं है क्योंकि उसने 2012 में राकांपा की ओर से चुनाव लड़ा था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि यदि एनसीपी की ओर से चुनाव लड़ने के बाद निर्वाचित घोषित किया जाता है तो अपीलकर्ता भाजपा का विधायक होगा। पैराग्राफ संख्या 2 में भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ संख्या 2 में व्यक्त की गई कानून की भावना को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को वह राहत नहीं दी जो उसे चाहिए थी कि उसे निर्वाचित घोषित किया जाए ।

28. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची किसी चुनाव याचिका के निर्णय पर लागू नहीं होती है। उन्होंने अधिनियम की धारा 53 (2) पर निर्भर करते हुए कहा कि अपीलकर्ता को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी/निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित किए जाने के बाद वह मैदान में एकमात्र व्यक्ति था। अधिनियम की धारा 101 में याचिकाकर्ता को विधिवत निर्वाचित घोषित करने का प्रावधान है यदि उच्च न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता को अधिकांश वैध वोट प्राप्त हुए हैं।

29. अधिनियम की धारा 80(ए) के अनुसार उच्च न्यायालय के पास चुनाव याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि चुनाव याचिका पर सुनवाई करने वाला उच्च न्यायालय एक 'प्राधिकरण' नहीं है और अधिनियम के तहत चुनाव याचिका पर सुनवाई करते समय यह उच्च न्यायालय बना रहता है। (देखें टी. दीन दयाल बनाम ए.पी. उच्च न्यायालय, *1997 (7)* एससीसी *535* पृष्ठ *540* पर)। इस न्यायालय ने हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी, *2001 (8)*

एससीसी ***233*** पृष्ठ ***244*** में राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखा ,यह निर्णय लिया गया कि चुनाव याचिका पर विचार करने का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्राधिकार का गठन करने और इसे उच्च न्यायालय को प्रदान करने के माध्यम से नहीं है। यह उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार है चुनावी विवादों को सुनने और निर्णय लेने के लिए। इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि चुनावी विवादों का फैसला होने पर उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति छीन नहीं ली जाती है। धारा 53 (2) निर्वाचन अधिकारी को प्रदत्त एक शक्ति है किसी उम्मीदवार को तब निर्वाचित घोषित करना जब उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर हो। उच्च न्यायालय की शक्ति धारा 53 (2) द्वारा सीमित नहीं है। उच्च न्यायालय ने उत्पन्न होने वाली एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पर विचार किया है किसी एक दल के उम्मीदवार द्वारा पक्ष परिवर्तन करने के बाद निर्वाचित घोषित किया जाना। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं और हमारा उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है।

30. उपरोक्त कारणों से, सिविल अपील खारिज़ की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अपील खारिज़।

यह अनुवाद आर्टिफ़िशयल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।